हिन्दी साप्ताहिक

Title Code:- UTTBIL00534

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -01 ♦ अंक-32 ♦देहरादून - रविवार 08 जून 2025 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्यः 1/-

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, बदरीनाथ मास्टर प्लान को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित धामी कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई।

बुधवार को देहरादून में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने यह जानकारी दी। बैठक में पास प्रस्तावों में शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा।

परिवहन विभाग में पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को एसएनए अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया, 50 प्रतिशत यानी गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए। परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ था, हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया।

कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पर जोकि कॉन्स्टेबल लेवल के हैं पहले उनकी परीक्षा अलग–अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ कराई जाने का निर्णय लिया गया।

कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूर्व बने ढांचे के 62 पदों के साथ अब 15 पद नए सर्जित किए गए।

गृह विभाग में भारतीय न्याय संहिता में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा गृह विभाग के मानवाधिकार में 47 पद थे, 12 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

कोविड को लेकर राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी

देहरादून। देशभर में कोविड–19 की स्थिति जहां इस समय नियंत्रण में है, वहीं उत्तराखंड में भी संक्रमण को लेकर हालात पूरी तरह सामान्य हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। संभावित जोखिमों से बचाव और सतर्कता के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार यह विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, अस्पतालों में आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में फिलहाल कोविड को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी संभावित जोखिम के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। इसी क्रम में प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों को सक्रिय मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोविड–19 को लेकर किसी खतरे की स्थिति घोषित नहीं की गई है। न ही कोई नया वेरिएंट सक्रिय रूप से फैल रहा है। संक्रमितों में भी केवल मामूली लक्षण पाए जा रहे हैं और वे सामान्य इलाज से घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी संभावित खतरों से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि, ऑक्सीजन, दवा और उपकरण पूरी तरह चालू रखने को कहा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाएं और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रहें।

सचिव ने निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण और कोविड के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए। सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और लैब्स प्रतिदिन आईएचआईपी पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करें। आईसीएमआर के कोविड–19 परीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार जांच कराई जाए। एसएआरआई और आईएलआई मामलों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी एसएआरआई मामलों की जांच अनिवार्य रूप से हो। स्वास्थ्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। सतर्कता और सहयोग से ही हम भविष्य में भी कोविड जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

भारी वर्षा होने के बावजूद गांधी पार्क के योग शिविर में जुटे साधक

संवाददाता देहरादून। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा बुधवार की सुबह गांधी पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। योगाचार्य आचार्य अरुण कुमार ने योग शिविर का शुभारंभ करते हुए योग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की कला सिखाता है। योग से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समृद्धि प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में योग को अपना ले तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। योग शिविर आरंभ होने से पूर्व भारी बरसात हुई। लेकिन आयोजकों और साधकों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। योग शिविर का शुभारंभ चिरंजीव भगवान परशुराम के चित्र पर मार्ल्यापण के साथ आचार्य अरुण कुमार योगाचार्य, महासभा अध्यक्ष पंडित मनमोहन शर्मा, लालचंद शर्मा, विपिन जोशी, सुधीर कुमार, राम सिंह, उमाशंकर शर्मा और महासभा के समस्त पदाधिकारियों ने सामूहिक रुप से किया।

आढ़त बाजार के निर्माण कार्य में लाएं तेजी: तिवारी

संवाददाता देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बुधवार को बैठक में आढ़त बाजार के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारी ने कहा कि आढ़त बाजार के कार्य में साठ प्रतिशत प्लॉटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। प्लॉटिंग, एसटीपी, पार्किंग का शेष कार्य एक माह में पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने हुडको से लोन स्वीकृत करवाने की कार्यवाही जल्द पूरी करने, सभी भूखंडों के लिए कन्ट्रोल डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। ताकि आढ़त बाजार की दुकानों में एक रूपता रहे। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों के साथ संयुक्त बैठक होगी।

राजधानी का आपदा कन्ट्रोल, संसाधन व प्रतिक्रिया होनी चाहिए ए क्लास:डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने बुधवार को आपदा परिचाजन केन्द्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए आपदा कन्ट्रोलरूम की दीवारों को जिले के तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के जीआईएस मैप से सुस्जित किया जाए।

आपदा परिचालन केन्द्र को डिजिटल कन्ट्रोलरूम में स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। डीएम ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि मानसूनकाल में त्वरित रिस्पांस हेतु एनएच, लोनिवि, यूपीसीएल, जलसंस्थान के जेई दो टाईम सुबह एवं शाम एक–2 घंटा आपदा परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहेंगे तथा अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा कन्ट्रोलरूम के वायरलेस सेट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। मुख्यमंत्री के आपदा की घटना पर दें त्वरित प्रतिक्रिया देने के निर्देश पर डीएम ने अपने एकीकृत आपदा कन्ट्रोलरूम की नब्ज जांची तथा त्वरित प्रतिक्रिया के निर्देश दिए। डीएम ग्राउंड जीरो पर उतरकर आला अधिकारियों को प्रोक्टिव रोल में रहने के निर्देश दिए हैं। जन शिकायत निवारण या प्रतिकूल स्थिति नियंत्रण हेतु प्रतिदिन मॉनिटिरिंग। मानसून सीजन के दृष्टिगत पेयजल सम्बन्धी 07, यूपीसीएल, लोनिवि, एनएच के 3, फोरेस्ट, पुलिस के 02 सक्षम स्तर अधिकारी प्रतिदिन हाजिर होंगे। डीएम ने निर्देश दिए कि अपनी राजधानी का कन्ट्रोल संसाधन व प्रतिक्रिया ए क्लास होना चाहिए। वहीं जिले के आपदा कन्ट्रोलरूम जल्द ही डिजिटल करने की तैयारी है। डीएम ने निर्देश दिए कि आपदा प्राधिकरण की समस्त रिक्तियां पूर्णतः भरी जाएं।

सम्पादकीय

महकती खुशियां,चहंकते गांव

ग्राम: भारतस्य हृदयम्, तत्रैव निहितं बलम्।
पर्यटनं च समृद्ध्यर्थं, ग्रामे विकसनं शुभम्।।
कृषका: ग्रामवासिन:,तेषु भारतस्य प्राण:।
पर्यटनं तेभ्य: लाभाय,विकासो निश्चयो भवेत्।।

अर्थात्
गांव में भारत का हृदय बसता है, और उसमें ही उसकी शक्ति निहित है।पर्यटन के माध्यम से जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, तो राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित होती है।

भारत की असली पहचान उसके गांवों में है। ग्रामीण पर्यटन से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है,बल्कि लोक संस्कृति, लोक परंपरा का सम्यक निर्वहन होता है। जिससे वैविध्यपूर्ण साहचर्य समरसता को प्राप्त हो सुदृढ़ होता है,प्राकृतिक सौंदर्य जीवंत हो उठता है।

किसान और गांववासी भारत के प्राण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत सामंजस्य को संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के समांग अभिवृद्धि का निरंतर प्रयास आवश्यक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। ग्रामीण पर्यटन का विकास उनके लिए और लाभकारी बनता है, जिससे सर्वांगीण विकास होता है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास से ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। इसके अलावा,पर्यटक भारतीय गांवों की प्राचीन परंपराओं,हस्तशिल्प, कला,संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होता है।

देवभूमि उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन समृद्ध हों, इसलिए ग्राम का विकास आवश्यक है।हमारे गांव के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के उपयोग के सुनियोजित उपयोग से हमें आर्थिक संवृद्धि पाना है।पहाड़ के जंगलों में पैदा होने वाले शुद्ध शहद से लेकर सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाने वाला आर्गेनिक मंडुआ, झंगोरा, गहथ,राजमा और हैंडमेड ऊनी वस्त्र से लेकर हैंडिक्राफ्ट तक सभी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इनको वैश्विक पहचान दिलानी है।इनकी बिक्री के लिए ई-कामर्स प्लेटफार्म पर ब्रांडिंग करनी है।राज्य के समग्र विकास के लिए,गांवों की आर्थिकी मजबूत की जानी जरूरी है।

पहाड़ के गांवों के सौहार्दपूर्ण, स्निग्ध मधुर अतीत की पुन: रौनक लौटानी है, रिश्तों में जीवंतता लानी है। पुरातनता और प्रगतिशीलता के सामंजस्य से सुख, समृद्धि ,समरसता लानी है। पहाड़ के गांव की आर्थिक संवृद्धि के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अपने प्रयास जारी रखने हैं। पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण और वनौषधियों के प्रसंस्करण से आर्थिक संवृद्धि लाकर देवभूमि के हर घर में खुशियां लानी है स्वरोजगार और स्वाध्याय की धुन जगानी है।

गांव का सर्वोन्मुखी विकास भारत जैसे देश का आधारभूत प्रगति का सर्वप्रमुख अवयव है।गांव गांव हरतरफ खुशियां हों,चहंकते चेहरे हों,महकता अपनापन हो, यही कामना है।उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण संवृद्धि ,ग्रामीण पर्यटन के विकास व गांवों की आत्मनिर्भरता हेतु हमारे प्रयास अहर्निश जारी रहेंगे।।

जय देवभूमि उत्तराखण्ड!!जय भारत !!

डॉ.गार्गी मिश्रा

सजा देने का काम पुलिस का नहीं

अजीत द्विवेदी

भारत में या किसी भी सभ्य समाज में मुठभेड़ में या पुलिस और न्यायिक हिरासत में आरोपियों या अपराधियों का भी मारा जाना समूची व्यवस्था के ऊपर धब्बा होता है। यह अपराध न्याय प्रणाली और समाज व्यवस्था पर कलंक है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप चाहे जितने भी गंभीर हों लेकिन उसे सजा देने का काम पुलिस का नहीं है। उसे कानून के हिसाब से अदालत से सजा मिलेगी। पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है। और पुलिस की इन मासूम कहानियों का भी कोई अर्थ नहीं होता है कि हथकड़ी में बंद आरोपी ने पुलिस वालों से हथियार छीन लिए या भागने की कोशिश की और इस क्रम में पुलिस के हाथों मारा गया। इस तरह की मनोहर कहानियां समूची न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाली होती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अदालतें आमतौर पर इन कहानियों पर यकीन कर लेती हैं। यह अच्छा है कि महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे की इनकाउंटर में हुई हत्या की कहानी पर हाई कोर्ट को यकीन नहीं हुआ है। अदालत ने कहा है कि पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। परंतु जब अदालतें पुलिस की कहानियों पर यकीन नहीं करती हैं तब भी थोड़ी बहुत फटकार या सख्ती के बाद बात आई गई हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती है। ध्यान रहे भारत में फर्जी मुठभेड़ को अपराध और मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पुराने आंकड़े के मुताबिक 2002 से 2017 के बीच भारत में 1,728 फर्जी इनकाउंटर हुए थे। बहरहाल, असली मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ होती है या नक्सलियों के साथ होती है। असली मुठभेड़ दंतेवाड़ा में होती है, जहां बहादुर जवान जान गंवाते हैं। असली मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में होती है, जहां इस साल जुलाई में 10 जवान शहीद हुए हैं। असली मुठभेड़ मुंबई पर हुए आतंकी हमले के समय हुई थी, जिसमें मुंबई पुलिस के अनेक डेकोरेटेड और जांबाज अधिकारी शहीद हुए थे। इस राज्य या उस राज्य की पुलिस जो मुठभेड़ करती है, जिसमें किसी पुलिस वाले की बांह में या किसी की जांघ में गोली लगती है वह आमतौर पर फर्जी होती है। अगर राज्यों की पुलिस की एसटीएफ या एटीएस के ये जवान इतने ही जांबाज हैं तो इनको तत्काल बस्तर और दंतेवाड़ा में या कश्मीर और मणिपुर भेजा जाना चाहिए।हकीकत यह है कि राज्यों में बनी ज्यादातर एसटीएफ या एटीएस का काम कानून व्यवस्था पर राज्य की सरकारों के लिए धारणा बनाने या धारणा को नियंत्रित करने का हो गया है। जब कानून व्यवस्था का सवाल उठता है और लोग नाराज होते हैं तो ये लोग कुछ आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराते हैं। इसके लिए उन्हें इनाम इकराम मिलते हैं। समाज में कुछ लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वे एक भस्मासुर पैदा कर रहे हैं, जिसका शिकार वे खुद भी हो सकते हैं।

बहरहाल, अभी देश मुठभेड़ की तीन घटनाओं को लेकर आंदोलित हैं। कहीं कहीं लोग रोमांचित भी हैं। लेकिन लोगों का क्या है! ये तीन प्रतिनिधि घटनाएं हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश की घटना है, दूसरी महाराष्ट्र की है और तीसरी तमिलनाडु की है। यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत की एक जैसी कहानी है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले एक डकैती हुई, जिसमें शामिल एक कथित आरोपी मंगेश यादव को यूपी पुलिस की एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के बाद की जो तस्वीरें मीडिया में आईं उसमें टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी हवाई चप्पल में ही थे और किसी ने भी मुठभेड़ में पहनी जाने वाली कॉम्बैट ड्रेस नहीं पहनी थी। इसे लेकर खूब मजाक बना। लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया।

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगेश यादव की मौत का मामला उठाया और दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह के बच जाने का जिक्र किया। इसके बाद मीडिया में ठाकुरवाद बनाम यादववाद की बहस शुरू हुई।

क्या फिलिस्तीन शत्रु-राष्ट्र है?

संजय पराते

छत्तीसगढ़ एक बार फिर गलत कारण से चर्चा में है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और प्रशासन के रवैए से और भाजपा सरकार की चुप्पी से यह प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे देश और यहां के नागरिकों के लिए क्या फिलिस्तीन शत्रु-राष्ट्र है?

इससे पहले जून में छत्तीसगढ़ तब चर्चा में आया था, जब भाजपा सरकार के आने के तीन दिन बाद ही उत्तरप्रदेश से आए तीन पशु व्यापारियों और परिवहन कर्मियों की आरएसएस और भाजपा से जुड़े गौ-गुंडों ने हत्या कर दी थी। यह मॉब-लिंचिंग का नहीं, बल्कि हत्या का सुनियोजित मामला था। यह ऐसा मौका था, जब भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दे सकती थी कि उसके राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होगा और जाति-धर्म से परे सभी नागरिकों से समान व्यवहार होगा और कानूनी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इसके विपरित, सरकार द्वारा गठित एक एसआइटी के जरिए सभी मृतकों द्वारा आत्महत्या किए जाने का फर्जी निष्कर्ष निकालकर वास्तविक हत्यारों को बरी कर दिया गया। इस घटना का पूरे देश में विरोध हुआ था, लेकिन भाजपा और उसकी सरकार को कोई फर्क पडना नहीं था।

अब 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नवी के दिन बिलासपुर में 5 मुस्लिम नौजवानों को घरों और मोहल्ले में फिलिस्तीन का झंडा लगाने के कथित अपराध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(2), जो देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्यों से संबंधित है और जिसके लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस शहर में हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी माना जाता है, क्योंकि प्रदेश का उच्च न्यायालय यहां पर है और इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि पूरी घटना उच्च न्यायलय के नाक के नीचे हुई है। ये गिरफ्तारियां संघी गिरोह से जुड़े लोगों और संगठनों की इस शिकायत के बाद की गई थी कि फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले लोग आतंकवादी हैं और ऐसा कृत्य देशद्रोह है। पूरे मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम का बनाकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आग उगलने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किए गए थे। धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले नागरिक मंच के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए कड़े प्रतिरोध के बाद जिला प्रशासन को गिरफ्तार युवकों को जमानत देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्मादी-हिंदू संगठनों के दबाव में गिरफ्तार युवकों को जेल में ही रखने की कोशिश में सिटी मजिस्ट्रेट 24 घंटों तक लुकाछिपी का खेल खेलते रहे और कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे। ये उन्मादी संगठन मुस्लिमों को आतंकवादी बताकर उन्हें बिलासपुर (और छत्तीसगढ़) में न रहने देने तथा मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने और अपनी रक्षा के लिए हिंदू समाज का सशस्त्रीकरण करने की गैर-कानूनी बात खुले तौर पर आम सभाओं में कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार के संरक्षण के चलते इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह एक उदाहरण है कि भाजपा शासित राज्यों में किस प्रकार मुस्लिम त्योहारों को भी उन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही हमले मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में भी हुए हैं, हो रहे हैं। मोहर्रम के मौके पर इसी जुलाई में जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्यप्रदेश और झारखंड में भाजपा तथा विहिप नेताओं की शिकायतों पर यूएपीए तथा बीएनएस के अंतर्गत मामले दायर किए गए हैं, गिरफ्तारियां की गई है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती बातें फैलाकर समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का कोई भी मौका भाजपा छोड़ना नहीं चाहती। नफरती बातें करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां कचरे की टोकरी में पड़ा हुआ है और यहां का उच्च न्यायालय इन सब घटनाओं का मूकदर्शक बना हुआ है, जो पिछले एक दशक में न्यायपालिका के क्षेत्र में आई गिरावट का ही प्रतीक है। पूरी दुनिया के लिए फिलिस्तीन आज राजनैतिक सवाल है। 20 सदी के अंत तक जहां दुनिया के तमाम पराधीन देश राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, 21वीं सदी में आज भी फिलिस्तीन एक ऐसा देश है, जो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए और इजरायल के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए लड़ रहा है और जिसे दुनिया के उन सभी लोगों, समुदायों और संगठनों का समर्थन प्राप्त हैं, जो शांति, न्याय और आजादी के हक में है और यह समझते हैं कि फिलिस्तीन ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीनियों का है, जिस प्रकार भारत भारतवासियों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का, और जो इसीलिए फिलिस्तीनी भू-भाग को हड़प-हड़पकर वहां इजरायली बस्तियां बसाने की इजराइली सरकार की विस्तारवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इजरायल ने 1967 के बाद से फिलिस्तीन के पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पूर्वी येरूशलम पर कब्जा करके अपने भू-भाग का विस्तार किया है।

गर्मियों में करें इन स्वास्थ्यवर्धक जूस का सेवन, आसान हैं इनकी रेसिपी

मौसम का मिजाज बदलने लगा है और गर्मियां जल्द ही दस्तक देने वाली है। ऐसे में मौसमी और ताजे फलों का जूस पीना बहुत स्वास्थ्यवर्धक और रिफ्रेशिंग होता है। हालांकि, अगर आप गर्मियों में खुद को हाइड्रेट और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मार्केट में मिलने वाले जूस की बजाय घर में ही कुछ स्वादिष्ट जूस बनाकर पिएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जूस रेसिपी बताते हैं, जिनका गर्मियों में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।

कीवी और खीरे का जूस

चुभनभरी गर्मी से बचाने में कीवी और खीरे के जूस का सेवन मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे और दो कीवी को धोकर छिलें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक जूसर में बर्फ के टुकड़े, ठंडा खीरा, ठंडी कीवी, थोड़ा पानी, एक चुटकी काली मिर्च, थोड़ा नमक और कदूकस किया हुए अदरक डालें और इस मिश्रण को पीसने के बाद गिलास में डालकर पिएं।

संतरे और तुलसी का जूस

संतरे और तुलसी के मिश्रण से बनने वाला यह जूस न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दो से तीन संतरे छिल लें, फिर इन्हें एक जूसर में कुछ तुलसी की पत्तियों, शहद और बर्फ के टुकड़े के साथ ब्लेंड करें। इसके बाद इस जूस को छानकर गिलास में डालें, फिर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इस जूस में नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

तरबूज और अदरक का जूस

तरबूज और अदरक का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एक जूसर में तीन चौथाई गिलास तरबूज का रस, दो चम्मच नींबू का रस, एक चौथाई चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और चुटकी भर कुटी काली मिर्च डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आपको ये कम मीठा लग रहा है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। अंत में इस जूस में बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर इसका सेवन करें।

मैंगो लाइम जूस

मैंगो लाइम जूस बनाने के लिए सबसे पहले दो कप कटे हुए आम को आधा कप नींबू के रस और एक कप ठंडे पानी के साथ मिक्सी में पीस लें। अब एक सॉस पैन में आधा कप चीनी और एक कप पानी को उबालें और जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे आम वाले मिश्रण के साथ मिलाएं। इसके बाद इस तैयार मैंगो लाइम जूस को गिलास में भरे और इस पर कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर इसे पिएं।

दिनचर्या में शामिल करें एरोबिक एक्सरसाइज, मजबूत होंगी मसल्स

कोरोना के बाद हर व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहता है। जिसके लिए वे अपनी जीवन शैली में सुधार कर रहे हैं। अपने शरीर को स्वस्थ व फिट रखने के लिए जहाँ युवा जिम का सहारा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएँ और युवतियाँ अपने शारीरिक सौष्ठप को बनाए रखने के लिए घर पर ही कई प्रकार की एक्सरसाइज कर रही हैं। इनकी बदौलत ये अपने शरीर को पूरी तरह से फिट और तन्दुरुस्त रख रहे हैं। यदि आप जिम में नहीं जा रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में एरोबिक एक्सरसाइज शामिल कर मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। एरोबिक एक्सरसा. इज के लिए आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से आप इसे कर सकते हैं। आपकी हृदय प्रणाली को मजबूत बनाने में एरोबिक एक्सरसाइज बहुत मददगार साबित होती है।

आइए डालते हैं एक नजर उन एरोबिक एक्सरसाइज पर जो आपकी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती हैंः

सीढ़ी चढना

सीढ़ी चढना फैट और कैलोरी बर्न करने का शानदार तरीका है। यदि 180 एलबी का शख्स एक घंटे तक मध्यम गति से सीढियाँ चढ़ता-उतरता है, तो उसकी करीब 600 कैलोरी बर्न हो सकती है। हाई लेग लिफ्ट शामिल होने के कारण सीढियां चढने से, नॉर्मल वॉक करने के मुकाबले अधिक मसल्स का यूज होता है। हालांकि सीढ़ी चढने से जोड़ों पर अधिक वजन और दबाव आ सकता है, इसलिए घुटनों की समस्या वाले लोग इसे करने से बचें।

पैदल चलना या टहलना

रोजाना टहलने से हृदय रोगों, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन का खतरा कम हो सकता है। साथ ही इससे पैरों की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके लिए आप सुबह-शाम सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट के लिए टहल सकते हैं। इसके प्रतिदिन 1000 कदम चलने से भी अपने आपको फिट रख सकते हैं। धीरे-धीरे करके आप इन कदमों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती हैं। टहलने के दौरान सही जूते पहनें और तेजी से सांसे लेने की कोशिश करें। साथ ही अपनी क्षमता से अधिक चलने का प्रयास न करें। इससे घुटनों या पैरों में चोट लग सकती है।

स्विमिंग

बहुत से लोगों को स्विमिंग करना अच्छा लगता है। इससे मांसपेशियों को टोन करने में मदद मिलती है साथ ही यह फेफड़ों की मजबूती के लिए बेहतर रहता है। आप पूल में सही तरीके से स्विमिंग सूट पहनकर जा सकते हैं। इसे आप ट्रेनर की मदद से कर सकते हैं। तैराकी से आपको ज्यादा चोट लगने का डर नहीं होता है लेकिन अगर आप पहली बार स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ट्रेनर की मदद लेनी होगी। इसे आप रोज आध I घंटे तक करें। इन 30 मिनटों में आप को 3 बार ब्रेक लेना चाहिए अर्थात् हर 10 मिनट बाद आप कुछ देर के लिए सुस्ता लें।

जुम्बा

जुम्बा एक एरोबिक डांस शैली है, जिसकी मदद से शरीर के सभी हिस्सों को टोन करने में मदद मिलती है। इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है और शरीर सुडौल बनता है। इससे तनाव दूर रहता है। इस दौरान आप किसी संगीत पर जुम्बा डांस कर सकते हैं। इसे आप सप्ताह में 1 से 3 बार 60 मिनट के लिए कर सकते हैं। डांस के समय आरामदायक जूते पहनें और हर 15 मिनट बाद ब्रेक लें और पानी पिएं। साथ ही शुरुआत में ट्रेनर की मदद से जुम्बा करने का प्रयास करें ताकि चोट से बच सकें।

जॉगिंग या दौडना

जॉगिंग या दौडना प्रभावी एरोबिक व्यायाम है। इससे मांसपेशियों का विकास और पूरे शरीर के अंगों में रक्त संचार उचित ढंग से होता है। इससे कैलोरी को तेजी से घटाने और मूड को सही करने में मदद मिलती है। इसके लिए सही जूते पहन लें और सुबह-शाम आधे घंटे के लिए दौड़ें। इसके लिए आप हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए धीरे-धीरे चलने का प्रयास करें। हालांकि दौडने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें।

रस्सी कूदना

रस्सी कूदने से आपके हाथों और पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। साथ ही हृदय प्रणाली और सांसों की समस्या भी कम हो जाती है। कहते हैं रस्सी कूदने से लंबाई भी बढ़ जाती है। इसे आप सप्ताह में आप 3 से 5 बार 15 मिनट से 25 मिनट के लिए कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन इनडोर या आउटडोर एक्टिविटी है। इसके लिए आप जिम के जूते पह. नकर रस्सी ले लें और पैरों को एक बराबर सीधी रेखा में रखें। रस्सी को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और फिर पैरों को एक साथ उठाकर कूदें और वापस जमीन पर आएं। उस दौरान बहुत अधिक कूदने का प्रयास न करें। इससे आपको चोट लग सकती है। रस्सी कूदने से पहले जॉगिंग जरूर कर लें। साथ ही हर 15 सेकेंड के बाद ब्रेकअप लें और फिर अगले सेट को शुरू करें। अगर आप पहली बार रस्सी कूद रहे हैं, तो इसे केवल 30 सेकेंड के लिए कूदें।

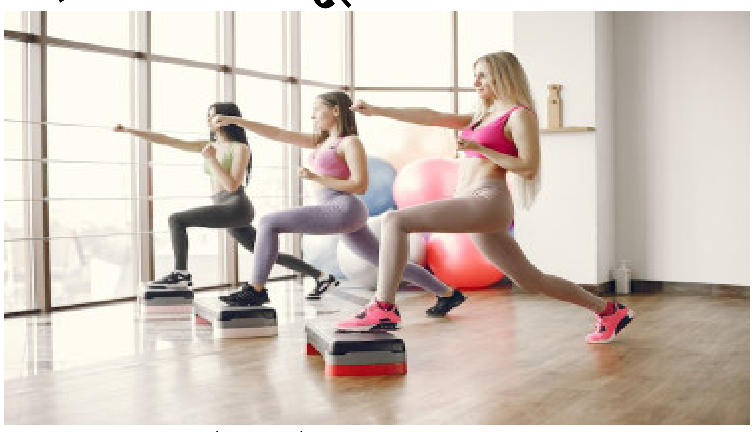

शरीर को मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं ये हस्त मुद्राएं, ऐसे करें अभ्यास

अममून लोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम घर में ही कुछ आसान योग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करके भी पूरा किया जा सकता है? कई ऐसी हस्त मुद्राएं हैं, जो न सिर्फ प्राकृतिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकती हैं बल्कि शरीर में लचीलापन भी ला सकती हैं। आइए आज आपको कुछ ऐसी हस्त मुद्राओं के अभ्यास का तरीका बताते हैं।

गणेश मुद्रा

सबसे पहले योगा मैट पर पद्मासन या फिर किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को छाती के सामने लाकर हथेलियों को एक-दूसरे के ऊपर रखें। इसके बाद दोनों हथेलियों की उंगलियों को मोडकर एक टाइट ग्रिप बनाएं, फिर हाथों की अवस्था को बदलें यानि जो हाथ ऊपर था उसे नीचे और नीचे वाले हाथ को ऊपर की ओर लाएं। हाथों के स्थान को 15 मिनट तक ऐसे ही बदलते रहें।

वरूण मुद्रा

वरूण मुद्रा के लिए सबसे पहले योगा मैट पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पर रखें कि हथेलियां आकाश की तरफ हों। इसके बाद अपनी कनिष्ठ उंग. ली को अपने अंगूठे की नोंक से मिलाएं और बाकि उंगलियों को सीधा रखें। अब अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना 20 से 25 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करें।

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर पद्मासन की मुद्रा में बैठें। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। इस दौरान हथेलियां आकाश की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद अपने हाथों की सबसे छोटी उंगली और अना. मिका उंगली को अंगूठे के नोक से छूएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। फिर अपनी दोनों आंखों को बंद करें और इस मुद्रा में 20-25 मिनट तक रहने की कोशिश करें।

पृथ्वी मुद्रा

सबसे पहले योगा मैट पर पद्मासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब सामान्य रूप से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों की अनामिका यानी रिंग फिंगर के ऊपरी हिस्से को अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलाएं और बाकि उंगलियों को सीधा रखें। फिर अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 30 से 45 मिनट तक इस मुद्रा में रहें।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने की विश्व ओलम्पिक दिवस के आयोजन की तैयारी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन के सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

देहरादून। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आगामी 23 जून 2025 विश्व ओलम्पिक दिवस के आयोजन की तैयारी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन के सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने कहा कि 23 जून को ओलम्पिक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में किस तरह के खेलों का आयोजन किया जायेगा इस पर अभी से कार्ययोजना बनायी जाए। उन्होंने अधिकारियों से खेलों को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं के साथ मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर आयोजन करने के निर्देश दिये।

खेल मंत्री ने ओलम्पिक दिवस के अवसर पर प्रतिभाग करने वाले बच्चों के पंजीकरण, प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को समापन समारोह में निमंत्रण देने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त कार्यक्रम को राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर आयोजित किया जा सके जिसमें उन्होंने मा0 मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही विश्व ओलम्पिक दिवस के आयोजन के हेतु दूसरी बैठक की जायेगी जिसमें आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय लिये जायेंगे।

मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विश्व ओलम्पिक दिवस के आयोजन ऐतिहासिक रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायतों के बच्चों, वृद्धजनों तक में खेलों के प्रति जनजागरूकता की अलख को जगाना है जिस हेतु विभाग तथा उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस अवसर पर महासचिव, उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन, डीके सिंह, सचिव, उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन, चेतन गुरूंग, निदेशक, खेल, प्रशान्त आर्य, तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

माण्डुवाला में बीच सड़क कार सवार की गोली मार कर हत्या

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में मंगलवार तड़के ढाई बजे एक कार सवार युवक को मोटरसाइकिल सवार युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामूली बहस के बाद सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना प्रेमनगर पर अभिषेक बर्तवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि आज तड़के जब वह अपने दोस्तों के साथ कार में पीपल चौक, माण्डुवाला में थे, तभी मोटरसाइकिल में आए दो व्यक्तियों में से एक ने कार के सामने की ओर से गोली चला दी। गोली कार सवार रोहित नेगी की गर्दन पर लगी। घायल रोहित को अपने दोस्तों के साथ ग्राफिक ऐरा अस्पताल, झाझरा लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने वाला आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी है।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना प्रेमनगर पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोहन सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया कि मृतक के दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ आरोपी अजहर त्यागी की जान पहचान थी।

ये भी पढ़ें:देहरादून में बीच सड़क हत्या, दोस्त की गर्लफ्रेंड के लिए बहस करने पर मारी गोली

रात में रोहित अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड और अन्य दोस्तों के साथ नयागांव दोस्त के घर पर थे। इसी दौरान उस लड़की को आरोपी का फोन आने पर रोहित और उसके दोस्तों की अजहर के साथ फोन पर बहस हुई। इसके बाद अजहर ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की जा रहीं है।

जनहित कार्यों की रीढ़ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: रेखा आर्या

देहरादून। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून जनपद में चयनित की गई 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सिर्फ रोजगार का एक माध्यम नहीं, बल्कि यह सेवा का एक बड़ा अवसर है। मंगलवार को वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में की गई। इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ तीन महीने के समय में पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अब विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में उच्च शिक्षित लड़कियां और महिलाएं आ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से विभाग की कार्य क्षमता और कुशलता में बढ़ोतरी होगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6330 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों यानी कुल मिलाकर 7052 पदों पर भर्ती की है। इनमें से सबसे पहले देहरादून जनपद में 17 कार्यत्रियों और 195 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।

पहाड़ों पर तहसीलों में कामकाज रहा ठप

देहरादून। राज्य में नौ जिलों में पूरी तरह तहसीलों में कामकाज ठप रहा। नैनीताल और देहरादून की पर्वतीय तहसीलों में भी पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ के कार्य बहिष्कार का बड़ा असर पड़ा। राजस्व पुलिस का काम वापस न लेने और बिना संसाधनों के फार्मर रजिस्टर अंश निधारण का काम कराने पर संघ ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्व सेवक संघ ने तीन जून और चार जून को पूरी तरह कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके तहत पहले दिन पटवारियों ने काम नहीं किया। इसके कारण तहसीलों में प्रमाण पत्र समेत अन्य कार्यों के लिए आने वालों को बैरंग लौटना पड़ा। राजस्व पुलिस से जुड़े काम पूरी तरह ठप रहे। राजस्व सेवक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह मेहता ने संघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज कर सभी लंबित मांगों के निस्तारण की मांग की। कहा कि बिना संसाधनों के राजस्व पुलिस का काम करना संभव नहीं है। हाईकोर्ट भी साफ कर चुका है कि राजस्व पुलिस का काम सिविल पुलिस को सौंपा जाए। कहा कि अंश निर्धारण का काम पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना है। ये काम बिना संसाधनों के मोबाइल पर करना पड़ रहा है। मोबाइल पर काम करने में दिक्कत पेश आ रही है। इसके लिए सभी लोगों को बड़ी स्क्रीन वाले फोन, लैपटॉप, टैप जैसे उपकरण डाटा पैक के साथ उपलब्ध कराए जाएं। पदोन्नति को लेकर पटवारियों के पदोन्नति कोटे में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसके साथ ही अन्य सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए। ऐसा न होने पर चार जून के बाद आंदोलन की नई रणनीति को सार्वजनिक किया जाएगा। लगातार सरकार पर दबाव बना कर रखा जाएगा। विरोध जताने वालों में महामंत्री महिपाल पुंडीर, विनोद रावत, दिकपाल बोरा, गुलाब सिंह, श्याम सिंह तोमर, देवेंन्दर कंडारी, जगदीश परिहार, त्रिभुवन बोरा, अतुल, शिव सिंह आदि मौजूद रहे। यहां रहा कार्यबहिष्कार का असर देहरादून में चकराता, कालसी, त्यूनी, नैनीताल में धारी, कैंची, नैनीताल, बेतालघाट तहसील के क्षेत्र में कार्यबहिष्कार का असर रहा। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में कार्य बहिष्कार का असर रहा।

संविधान का खुला उल्लंघन कर रही सरकार: यशपाल आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। आज की तारीख में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायतें प्रशासक विहीन हैं। पंचायती व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उसके लक्षण ठीक नहीं हैं। चुनाव नहीं होने से प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में आर्य ने कहा कि विगत 27 मई से साढ़े सात हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें और 13 जिला पंचायतें लावारिश पड़ी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, न प्रशासक है और न निर्वाचित बोर्ड। राजभवन ने भी पंचायतीराज एक्ट में संशोधन विधेयक को वापस भेज दिया है। सरकार की ओर से पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छह महीने पहले चुनाव की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने का समय आने पर भी अब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही है। प्रत्येक पांच साल में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार आम मतदाता का है। ऐसे में बीजेपी सरकार अकारण विलंब करके उम्मीदवारों और वोटर्स के हक का गला घोट रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ग्राम सभाएं हमारी संस्कृति व समृद्धता की नींव है और इसके सशक्तीकरण का काम पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से होता आया है लेकिन आज सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है जिसका हम मुखरता से विरोध करेंगे।

सत्ता के स्वार्थ में यह स्थिति खड़ी की: हरीश

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज की तिथि में राज्य में पंचायतों का कोई ग्वाला-गोसाई नहीं रहा। सरकार के षड्यंत्र पूर्ण रवैये के कारण पंचायती राज एक्ट रसातल में चला गया, जो वास्तविक अर्थों में राज्य की पंचायती व्यवस्था के लिए सरकार निर्मित संवैधानिक संकट है। सत्ता के स्वार्थ ने यह दुःखद स्थिति खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इन संस्थाओं के अधिकारों को अर्थहीन कर रही है। सरकार पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियां छीनने और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करने का काम कर रही है। पंचायत चुनाव कब होंगे, कोई पता नहीं। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार अक्षम दिख रही है।

शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा आंदोलन का नोटिस

देहरादून। प्रमोशन में देरी से नाराज शिक्षकों ने आरपार की लड़ाई चेतावनी दी है। मंगलवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रदेश मंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती से मुलाकात कर आंदोलन का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि विभाग, शासन और सरकार के साथ विभिन्न स्तरों की वार्ताओं के बावजूद आजतक प्रमोशन नहीं हो पाए हैं। इस वजह से प्रदेश के सभी शिक्षकों में काफी रोष है। दो जून से शीतकालीन अवकाश वाले सभी स्कूलों में गैरशैक्षणिक कायों का बहिष्कार शुरू कर दिया गया है।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आर्फसेट प्रिंटर्श 64 नेशविला रोड देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादक:
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।